



उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास के स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन

Girijesh Kumar

Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

Dr. Manuj

Research Supervisor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: **10/04/2025**

Accepted: **25/04/2025**

Published: **30/04/2025**

Keywords: उत्तर प्रदेश, आधारभूत संरचना, विकास के स्तर, क्षेत्रीय भिन्नता, आर्थिक गतिविधि, पर्यावरणीय स्थिति, व्यापार का विस्तार.

ABSTRACT

उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के विकास के स्तरों में क्षेत्रीय भिन्नता का अवलोकन देता है। बुनियादी ढांचा विकास भारत की आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण प्रति वर्ष 7 से 8 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए एक पूर्व शर्त है, जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है। "आधारभूत संरचना, सामान्य रूप से, बुनियादी प्रणाली और सेवाओं को संदर्भित करती है जो देश या क्षेत्र या संगठन के लिए आवश्यक हैं। यह सुविधाओं के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत ढांचे के एक समूह को परिभाषित करती है जिसके बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि विकसित नहीं हो सकती है। बुनियादी ढांचा स्वयं अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक इनपुट हैं। यह श्रम और पूंजी सहित अन्य कारकों की उत्पादकता बढ़ाता है, इसकी पर्याप्तता उत्पादन में विविधता लाने, व्यापार का विस्तार करने और जनसंख्या वृद्धि से निपटने, गरीबी को कम करने और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाने की सफलता को निर्धारित करने में मदद करती है। लेकिन बुनियादी ढांचा सुविधाओं की कमी केवल आर्थिक विकास की गति को बाधित करती है, बल्कि पूरे देश में उत्पादकता में अंतर भी उत्पन्न करती है।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश का विकास एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की मांग करता है। इस विकास की यात्रा में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, और तकनीकी उन्नति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति है जो उस संस्था द्वारा बनाई गई थी जो वाणिज्य के वाहक के रूप में कार्य करती है। उनमें से कुछ सार्वजनिक हैं और कुछ निजी हैं। दोनों ही मामलों में यह रूपांतरणकारी की तरह भूमिका निभाती है जो संसाधन को आउटपुट या डायवर्सनरी में बदलने में मदद करती है और जो संसाधनों को गैर-उत्पादक में स्थानांतरित करने में मदद करती है।

एक देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक भिन्नता को कम करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक की रिपोर्ट (WDR) का निष्कर्ष है कि "आधारभूत संरचना का आर्थिक विकास और परिवारों के कल्याण से अच्छा तरह से जुड़ा और मजबूत संबंध है। यह उन देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा है जो एक दशक से समायोजित हैं और आधारभूत संरचना पर महत्वपूर्ण रूप से कम खर्च कर रहे हैं, और संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं के लिए जिनके पास बाजार अर्थव्यवस्था की सेवा करने के लिए महत्वपूर्ण नई आधारभूत संरचना की जरूरत है।"

दूसरे शब्दों में, आधारभूत संरचना में टिकाऊ संसाधन होते हैं जिनका उपयोग कई फर्मों और परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से किया जा सकता है। बुनियादी ढांचा आर्थिक एजेंटों को संसाधनों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। आधारभूत संरचना को संसाधन प्रवाह, संचार के लिए बातचीत की संभावनाओं के परिदृश्य के रूप में सोचा जा सकता है, पारस्परिक और अंतर-फर्म संपर्कों के साथ-साथ अन्य प्रकार के बाजार संपर्क। इस तरह हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा एक ऐसी क्षमता है जो संतुलित विकास की ओर ले जाती है।

अवसंरचना विकास संकेतकों का चयन

उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास के स्तर को निर्धारित करने में कुल 9 चर का उपयोग किया गया है। सड़क संपर्क और रेलवे स्टेशन हॉल्ट आवश्यक भौतिक अवसंरचना के प्रमुख कारक हैं जो उत्पादन के कारकों और विकास के स्तरों को बढ़ाते हैं। डाकघरों और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या उत्तर प्रदेश में संचार नेटवर्क विकास के स्तर को दर्शाती है। किसी भी क्षेत्र में वितरण कार्यालयों को मापने के लिए, प्रसार के दो संकेतक हैं: जनसंख्या (एक डाकघर के अंतर्गत) और एक डाकघर के अंतर्गत

क्षेत्र। प्रति डाकघर जनसंख्या डाकघर शाखाओं पर बोझ को दर्शाती है। एक डाकघर के अंतर्गत क्षेत्र इसकी पहुँच को दर्शाता है।

इस अध्ययन में एक डाकघर के अंतर्गत जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है। परिसर के भीतर पानी की सुविधा लोगों की पहुँच के भीतर पानी की उपलब्धता को दर्शाती है। बिजली मुख्य सहायक बिजली अवसंरचनाओं में से एक है और इसकी सुनिश्चित आपूर्ति उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ाती है।

एलपीजी आदर्श आधुनिक ईंधन है जिसने अप्रत्यक्ष रूप से कामकाजी उत्पादकता में सुधार किया है, खासकर महिलाओं के लिए क्योंकि भोजन मुख्य रूप से परिवार की महिला सदस्य द्वारा पकाया जाता है। इसलिए यह राज्य के विकास में एक सहायक चर भी है। बैंक सुविधाएँ और ऋण-जमा अनुपात वित्तीय अवसंरचना प्रणाली के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो अन्य चरों को मौद्रिक सहायता की आसान आपूर्ति को दर्शाते हैं।

अवसंरचनात्मक विकास संकेतकों का क्षेत्रीय वितरण: अंतर-जिला और अंतर-क्षेत्रीय विश्लेषण

1. कुल सड़क की लंबाई

अवसंरचनात्मक विकास कुल सड़क के मामले में अंतर-क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शाता है। 2001 में, लखनऊ (6.70) और गाजियाबाद (3.52) दो अत्यधिक विकसित जिले थे और 2011 में, लखनऊ (5.62), कानपुर (2.80) और वाराणसी (1.97) जैसे तीन जिले उच्च श्रेणी में आ गए। राज्य की राजधानी होने के नाते लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बेहतर सुख-सुविधाएँ हैं। 2001 में विकास की उच्च श्रेणी में केवल 5.71 प्रतिशत जिले आए, लेकिन 2011 में उनका हिस्सा बढ़कर 18.57 प्रतिशत हो गया। 2001 में लगभग 72.85 प्रतिशत जिले और 2011 में 44.28 प्रतिशत जिले मध्यम श्रेणी में सूचीबद्ध किए गए हैं।

रेलवे स्टेशन हॉल्ट की संख्या

जैसा कि तालिका 1 से स्पष्ट है, 2001 और 2011 में 5 जिले ऐसे थे जो प्रति 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन हॉल्ट के मामले में विकसित हुए। गाजियाबाद, कानपुर नगर, संतरा विदासनगर, वाराणसी और लखनऊ इस संदर्भ में अत्यधिक विकसित जिले हैं। दशक के अवधि में 14.28 प्रतिशत

जिले विकास की उच्च श्रेणी में आते हैं। 2001 में 29 जिले और 2011 में 28 जिले उत्तर प्रदेश के मध्यम रूप से विकसित जिले थे।

तालिका 1: उत्तरप्रदेश: रेलवेस्टेशनहाल्ट (2001-2011)

Category	2001		2011	
	No. of districts	%	No. of districts	%
Very High	5	7.14	5	7.14
High	10	14.28	10	14.28
Medium	29	41.42	28	39.99
Low	26	37.14	27	38.57
Very Low	--	--	--	--
Total	70	100	70	100

क्षेत्रीय वितरण में रेलवे स्टेशन हॉल्ट और टेलीफोन कनेक्शन की स्थिति

2011 में पश्चिमी जिले जैसे पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, जेपी नगर इत्यादि पश्चिमी क्षेत्र के मध्यम श्रेणी के जिले थे। 2001 में पूर्वी क्षेत्र में ग्यारह मध्यम विकसित जिले थे, अर्थात इलाहाबाद, बहराइच, बलिया, चंदौली, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर। 2011 में केवल आठ जिले इस श्रेणी में थे क्योंकि बहराइच और सुलतानपुर (नकारात्मक परिवर्तन) और जौनपुर (सकारात्मक परिवर्तन) जैसे कुछ जिलों ने अपनी स्थिति बदल दी है।

बाराबंकी, हरदोई, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव 2001 और 2011 में मध्य क्षेत्र के मध्यम विकसित जिले थे। 2001 में बुंदेलखंड क्षेत्र में इस श्रेणी में कोई जिला नहीं था, जैसा कि तालिका 4.3 से स्पष्ट है। 2001 में उत्तर प्रदेश के 26 जिले रेलवे स्टेशन हॉल्ट के मामले में पिछड़े थे और 2011 में यह संख्या बढ़कर 27 हो गई। तालिका 4.3 से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र ने इस संदर्भ में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई, दूसरी ओर मध्य क्षेत्र में फतेहपुर दोनों दशकों में एकमात्र पिछड़ा जिला है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 2001 से 2011 तक कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं।

टेलीफोन कनेक्शन

तालिका 2 से पता चलता है कि 2001 में केवल तीन जिले अर्थात लखनऊ (4.85), कानपुर नगर (3.84) और इलाहाबाद (2.83) अत्यधिक विकसित जिलों में थे और 2011 में हमीरपुर जिला इस श्रेणी

में शामिल हो गया, जबकि अन्य जिले समान रहे। उच्च श्रेणी में, 10 जिले थे जो 2011 में बढ़कर 14 हो गए। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी (1.01), ललितपुर (0.98), जालौन (0.81) और महोबा जिले (0.66) हैं। पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर (0.76), मऊ (0.74), फैजाबाद (0.74), मिर्जापुर (0.69), बलिया (0.59) और आजमगढ़ (0.51) जिले हैं। मध्य क्षेत्र में दो जिले हैं अर्थात बाराबंकी (0.63) और उन्नाव (0.59)। 2011 के दौरान उच्च श्रेणी में पश्चिमी क्षेत्र के मुजफ्फरनगर (0.99) और सहारनपुर (0.71) जिले हैं। 2001 और 2011 में क्रमशः 47 प्रतिशत और 34.28 प्रतिशत जिले मध्यम स्तर के विकास के अंतर्गत हैं।

तालिका 2: उत्तरप्रदेश: टेलीफोनकनेक्शन (2001-2011)

Category	2001		2011	
	No. of districts	%	No. of districts	%
Very High	3	4.28	4	5.71
High	10	14.28	14	20
Medium	33	47.14	24	34.28
Low	24	34.28	28	40
Very Low	--	--	--	--
Total	70	100	70	100

संचार क्षेत्र में विकास

2001 में, 24 जिले ऐसे थे, जिनमें संचार क्षेत्र में विकास का निम्न स्तर दर्ज किया गया था। 2011 में निम्न श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र के 13 जिले हैं, जैसे बागपत, औरैया, मथुरा, मेरठ, बिजनौर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, आगरा, कन्नौज, ज्योतिबा फुले नगर और मुरादाबाद। 28 जिलों में से पूर्वी क्षेत्र के 13 जिले हैं, जैसे वाराणसी, संतरविदासनगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बलरामपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, जो सबसे कम विकसित हैं। मध्य क्षेत्र में कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी जिले हैं जो निम्न श्रेणी में आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट एकमात्र ऐसा जिला है, जहां टेलीफोन कनेक्टिविटी कम है।

परिसर में जल सुविधा

रामपुर (2.01), बरेली (1.96), ज्योतिबा फुले नगर (1.88), गाजियाबाद (1.87), मेरठ (1.85), मुरादाबाद (1.84), पीलीभीत (1.80), मुजफ्फरनगर (1.56) और गौतम बुद्ध नगर (1.52) 2001 में अत्यधिक विकसित जिले थे, जैसा कि चित्र 4.13 में दिखाया गया है। 2011 में, मुजफ्फरनगर अपने स्थान से

फिसल गया, जबकि अन्य जिले बहुत उच्च श्रेणी में बने रहे। परिसर के भीतर पानी की सुविधा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक बेहतर तस्वीर दिखाती है, इसमें 2001 और 2011 में 7 जिले उच्च श्रेणी में हैं। पूर्वी क्षेत्र में 2001 में केवल देवरिया एक विकसित जिला था और 2011 में बलिया, बलरामपुर और मऊ जैसे तीन जिले विकास के संतोषजनक संकेत दिखाते हैं।

बिजली सुविधा

भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लगभग 58.5 मिलियन घरों में अभी भी ग्रिड बिजली की पहुँच नहीं है। कई घरों में वर्तमान सेवाएँ कम हैं, उन्हें प्रतिदिन चार घंटे से भी कम बिजली मिलती है। 2001 में, कुल घरों में से 55.8 प्रतिशत और 2011 में, कुल घरों में से 67.2 प्रतिशत घरों में बिजली पहुँची थी (गरुड़ और शर्मा, 2016)। प्रचुर, सस्ती और नियमित बिजली आपूर्ति की उपलब्धता विकास के लिए एक आवश्यक मानदंड है। जैसे कि आंकड़े 4.16 से स्पष्ट है, गाजियाबाद (2.70), वाराणसी (2.37), कानपुर नगर (2.24), गौतम बुद्ध नगर (2.23), लखनऊ (2.23), मेरठ (2.20), सहारनपुर (1.74) और आगरा (1.64) 2001 में अत्यधिक विकसित जिले थे।

तालिका 3: उत्तरप्रदेश: विद्युतसुविधा (2001-2011)

Category	2001		2011	
	No. of districts	%	No. of districts	%
Very High	8	11.42	8	11.42
High	9	12.86	8	11.42
Medium	24	34.28	29	41.41
Low	29	41.41	25	35.71
Very Low	--	--	--	--
Total	70	100	70	100

एलपीजी खपत

देश के सभी घरों में स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन की व्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि खाना पकाने के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करने वाले घरों की हिस्सेदारी 2001 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 60 प्रतिशत हो गई है, लेकिन 65 प्रतिशत उपभोक्ता शहरी घरों से हैं जबकि ग्रामीण भारत में केवल 11 प्रतिशत घर एलपीजी का उपयोग करते हैं। ग्रामीण घरों में जलाऊ लकड़ी का निरंतर उपयोग मुख्य रूप से जलाऊ लकड़ी

(पास के जंगलों और खेतों से) की आसान उपलब्धता, उच्च लागत और एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई और एलपीजी आउटलेट से सिलेंडर की उपलब्धता के कारण है। यहां भी, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) बीपीएल परिवारों तक एलपीजी की पहुँच बढ़ाने के प्रयास कर रही है, वैकल्पिक विकल्पों की संभावनाओं की जांच की जा रही है जैसे कि विद्युत प्रेरण कुकर स्टोव, और शहरी केंद्रों में पाइप गैस की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सिलेंडर जारी करना, जो कि बड़ी आबादी को स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा समाधान प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास को पूरक बना सकता है।

बैंकिंग सुविधा

चित्र 4 में दर्शाया गया है कि लखनऊ (3.31), कानपुर नगर (2.90), कानपुर देहात (2.83), गौतम बुद्ध नगर (2.24), गाजियाबाद (1.66), मेरठ (1.65), वाराणसी (1.64) और मथुरा जिले 2001 में उत्तर प्रदेश के आठ विकसित जिले थे। 2011 में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में बहुत अधिक विकसित हैं। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता पश्चिमी क्षेत्र में परिवारों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल रखने में सक्षम नहीं है। उच्च श्रेणी के अंतर्गत पांच जिले हैं, जिनकी संख्या 2011 में बढ़कर 9 हो गई और ये जिले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से हैं। 2001 में लगभग 47 प्रतिशत जिले और 2011 में 52 प्रतिशत जिलों में विकास की मध्यम दर थी, जैसा कि तालिका 4.9 में दिखाया गया है। पश्चिमी क्षेत्र में 2001 में 14 जिले थे और 2011 में 16 जिले थे, जिन्हें विकास के मध्यम स्तर में वर्गीकृत किया गया था। पूर्वी क्षेत्र में 2001 में 13 जिले थे और 2011 में 14 जिले थे।

बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने में क्षेत्रीय भिन्नता

बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के मामले में क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शाता है। परिवारों के बीच बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वालों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अलग-अलग दरों पर। 2001 में, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र और राज्य में औसत मूल्य लगभग 5 प्रतिशत थे। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम सेवाएँ दर्ज की गईं, जो केवल 4.4 प्रतिशत है। लेकिन 2011 में वृद्धि की दर पश्चिमी क्षेत्र (6.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक है, उसके बाद मध्य क्षेत्र (6.2 प्रतिशत) है और राज्य के पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम परिवर्तन दर्ज किया गया है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास में क्षेत्रीय भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, और मेरठ जैसे शहर शामिल हैं, आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर सड़क, रेल, और हवाई अड्डों की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो क्षेत्र को समृद्ध और विकसित बनाती हैं। दूसरी ओर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, और बलिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं, आधारभूत संरचना के विकास में पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्रीय भिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें ऐतिहासिक, आर्थिक, और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिकीकरण की अधिक संभावनाएँ होने के कारण यहाँ आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। इसके विपरीत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि पर अधिक निर्भरता और कम औद्योगिकीकरण के कारण यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास धीमा रहा है। हालांकि, राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में इन असमानताओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, और अन्य प्रमुख परियोजनाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी योजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोरों के विकास से भी क्षेत्रीय संतुलन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, अभी भी इन क्षेत्रों में समानता लाने के लिए निरंतर और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. जमाल, एच. और खान, ए.जे. (2023). क्षेत्रीय भिन्नता का बदलता स्वरूप। *पाकिस्तान विकास समीक्षा*, 42(2), 113-123।
2. इयिगुन, एम. एफ. और ओवेन, ए. (2014). आय भिन्नता, वित्तीय विकास और मैक्रोइकॉनॉमिक्स में उतार-चढ़ाव। *द इकोनॉमिक जर्नल*, 114 (495), 352-376।
3. रोड्रिगेज, ई. और ओरेगिया (2017). मेक्सिको में क्षेत्रीय विकास के विजेता और हारने वाले और उनकी गतिशीलता। *इन्वेस्टिगेशन इकनोमिका*, 66(259), 43-62।
4. चूआ. एच, वोंग, के.डब्लू और शेक, डीटीएल (2020). हांगकांग में सामाजिक विकास: सामाजिक विकास सूचकांक (SDI) द्वारा पहचाने गए विकास मुद्दे। *सामाजिक संकेतक अनुसंधान*, 95(3), 535-551।
5. माजुको, एस. और सुहरके, एम. (2021). यूरोप में स्वास्थ्य भिन्नताएँ, यूरोपीय श्रमबल सर्वेक्षणों से नई जानकारी। *जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ*, 65(9), 757-763।

6. राव और ब्रह्मा, सुलभा (2023). विकास योजना के उपकरण के रूप में क्षेत्रीय योजना। *अन्वेषक*, 3(1-2), 57-66।
7. पंडित, एम.एल. (2014). राज्यों में औद्योगिक आय की वृद्धि, 1960-69। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, 6 (2), 124-135।
8. कृष्णाजी, एन. (2015). बढ़ती दूरियाँ: एस.डी.पी. विविधताएँ 1961-98। *विकास और परिवर्तन में* (संपादित). राज, के.एन. बॉम्बे: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. राव, हेमलता (2017). भारत में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान और क्षेत्रीय भिन्नताओं के रुझान। *अर्थशास्त्र*, XIX(2), जून, 93-112।
10. संपत, आर.के. (2017). भारत में आय में अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ, 1951-71। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, IX(1), 1-9।
11. प्रकाश, एस. (2017). भारत में अवसंरचना सुविधाओं के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय भिन्नताएँ और आर्थिक विकास। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, 11(2), 173-195।
12. राव, सी.सी.एच. (2019). भारत में कम विकसित क्षेत्र की गरीबी और विकास की विशेषताएँ। *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक*, XIV (30-31-32), 11 अगस्त।
13. दास और दलवी (2021). छठी पंचवर्षीय योजना अवधी के लिए भारत में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास के पूर्वानुमान के लिए शिफ्ट और शेयर तकनीक का अनुप्रयोग। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, XIII (2), 187-200।
14. छीपा और सागर (2021). भारत में बैंकिंग विकास: क्षेत्रीय अंतरों के कारणों पर एक अध्ययन। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, XVIII (1), 86-89।
15. भारद्वाज, के. (2022). भारत में क्षेत्रीय विभेदन। *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक*, XVII (14, 15, 16) अप्रैल, 605-614।
16. चंद, महेश और पुरी, वी.के. (2023). भारत में क्षेत्रीय असंतुलन और भिन्नताएँ। *भारत में क्षेत्रीय नियोजन*, नई दिल्ली: एलाइड पब्लिशर्स लिमिटेड।
17. चंद, महेश और पुरी, वी.के. (2023). केंद्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण। *भारत में क्षेत्रीय नियोजन*, नई दिल्ली: एलाइड पब्लिशर्स लिमिटेड।
18. नायर, के.आर.जी (2023). भारत में अंतर-राज्यीय आय अंतर: 1970-71 से 1979-80। *मैन एंड डेवलपमेंट*, 5(2), 43-54।



19. सुअर, डेमन. (2014). उड़ीसा में विकास संकेतकों की पहचान और क्षेत्रीय भिन्नता। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, XVI(7), 108-121।
20. गुप्ता, दीपक. (2015). भारत में अंतर-राज्यीय औद्योगिक भिन्नताएँ: बदलता परिदृश्य। *भारतीय रिज़र्व बैंक के सामयिक पत्र*, 6 (1), 54-68।
21. देसाई, रोहित. (2016). क्षेत्रीय औद्योगिक विविधीकरण का बदलता स्वरूप: समय के साथ तुलना। *इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस*, XVII (1), 11-16।